नहीं किया अपितु जनसाधारण को तथा पशु-पक्षी को भी अत्यधिक नुकसान पहुंचाया करोड़ों रुपए की फसल चौपट हो गई । गेहूं, चना, इत्यादि की फसल शत-प्रतिशत नष्ट हो गई । कितने ही कुऐं धंस गये । हजारों की संख्या में बेचारे पशु पक्षी मर गये । मवेशियों का भारी मात्रा में नुक्सान हुआ । गरीब जनता के सैकड़ों झोपड़े गिर गये, विशेषकर राजगढ़ गुना तथा विदिशा जिला इस की चपेट में आया । इन जिलों में करोड़ों रूपयों का नुक्सान हुआ ।

ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण समय में केन्द्र सरकार को चाहिये कि वह ग्रसित जनता को अधिक से अधिक अनाज उपलब्ध करावे--लोगों को आर्थिक सहायता दी जाय। राज्य शासन द्वारा मांग की पूर्ति शीघ्र की जाय जिस से कि तत्काल प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य खोले जा सकें । प्रभावित क्षेत्रों की जनता से राजस्व वसूली, तकावी वसूली तथा बैंकों के ऋण की वसूली भी माफ की जाय अथवा स्थगित की जाय ।

जो भी थोड़ी सी फसल बची है उसे बचाने के लिये कीटनाशक औषधियां तत्काल ही भेजी जानी चाहिये और किसानों को मुफ्त वितरण होना चाहिये ।

इसी प्रकार देश के अन्य प्रदेश भी ओलावृष्टि से प्रभावित हुए हैं । केन्द्र सरकार को युद्ध स्तर पर इस समस्या पर विचार एवं कार्य करना चाहिये । इस समस्या पर सरकार क्या कदम उठा रही है, इत्यादि विवरण सदन में बताये ।

(iii) NEED FOR FIXING A MINIMUM PRICE FOR JAGGERY AND USING SUGARCANE FOR MANUFACTURING ALCOHOL.

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU (Chittoor): Under Rule 377, I am making a statement.

About 55 per cent of sugar cane in the country is converted into Jaggery. Almost all jaggery producers are either small or marginal farmers. Jaggery production has become a cottage or primary industry and it is absorbing lakhs of agricultural workers.

At present the Jaggery prices went so low that the prices are not even equal to cost of cultivation and, therefore, jaggery producers are getting a loss and agricultural workers continue to suffer.

I am glad to say that our Government has allowed export of jaggery to the other countries but the price is not rising.

I urge upon the Government to find out the reasons for it and help the agriculturists by fixing minimum price for the Jaggery and purchase the commodity so that the jaggery producers may not be put to losses.

I also request to start more sugar factories to consume more cane so that production of jaggery is reduced.

Manufacture of power alcohol is within the capacity of our Government. If licences are given for the manufacture of this commodity from sugarcane juice then this alcohol will be useful to run the transport vehicles as in other countries thereby reducing the import of diesel and other oil.

It is, therefore, requested to utilise sugar cane to manufacture power alcohol.

(iv) NEED FOR RELIEF MEASURES FOR FAMINE AFFECTED TEHSILS IN PALI DISTRICT OF RAJASTHAN.

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, कर्त्तव्य ने मुझे बाध्य कर दिया है कि मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पाली राजस्थान में पाली जिले की विशेष रूप से तहसील पाली में समस्त

[श्री मूल चन्द डागा]

गांवों और अन्य आदिवासी क्षेत्र के ग्रामीण अनु-जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की दयनीय एवं शोचनीय स्थिति की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकृष्ट करूं । पूरे तीन वर्ष बरसात न होने से गरीब लोग भूख के कगार पर खड़े हैं । सरकार ने अभी तक राहत कार्य इन क्षेत्रों में नहीं खोले हैं । लोगों ने अपने घर के पीतल के बर्तन तक वेच दिये हैं और कर्जा इतना ले लिया है कि उनको अब कहीं से और कर्जा नहीं मिल रहा है । अकाल राहत कार्य न खुलने से लोगों की क्रय शक्ति टूट गई है । लोग भयंकर अकाल की चपेट में हैं । कई गांवों में पेय जल तक उपलब्ध नहीं हैं । चारे की भारी कमी के कारण पशु भारी संख्या में मरने लगे हैं । सस्ता धान पर्याप्त मात्रा में गांवों में नहीं मिल रहा है । राजस्थान सरकार की आर्थिक स्थिति ऐसी दयनीय है कि काफी ओवर ड्राफ्ट ले चुकी है और नये अकाल राहत कार्य चालू करने में असमर्थ है । ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार को अविलम्ब कार्य-वाही करनी चाहिए ताकि कुछ राहत मिल सके ।

(v) NEED FOR STOPPING SOFT-STONE MINING IN MUSSOORIE.

श्री हर श चन्द्र सिंह रावत : (अल्मोड़ा) मसूरी भारतवर्ष की सुन्दरतम पर्यटक नगरी है । यह नगरी शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है जहां कि अच्छी क्वालिटी का सोफ्ट स्टोन पाया जाता है । इस सोफ्ट स्टोन के खनन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कई लोगों को खनन कार्य के लिए लीज पट्टे दिये गये हैं । इन लीज धारकों द्वारा खनन नियमों की सर्वथा अवहेलना कर खनन कार्य किया जा रहा है जिसे न तो भारत सरकार व न प्रान्तीय सरकार के माइनिंग विभाग के अधिकारियों द्वारा निर्धारित नियमों का अनुपालन करवाते हुए सुव्यवस्थित करने की चेष्टा की जा रही है । खनन किये गये क्षेत्र को पुनः रिक्लेम करने के कार्य पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप भयंकर भू-क्षरण हो रहा है । इस सोफ्ट स्टोन पर आधारित कई भट्टियां देहरादून शहर के वातावरण को प्रदूषित कर रहीं हैं । इन भट्टियों में किसी भी प्रकार की प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था नहीं है ।

प्रदूषण, भू-क्षरण तथा अव्यवस्थित तथा सारे खनन कार्य से शिवालिक की पहाड़ी पर स्थित सुन्दरतम मसूरी के लिए खतरा पैदा हो गया है । इस क्षेत्र की वनस्पति नष्ट हो रही है । पेयजल के श्रोत सूख रहे हैं । मसूरी की कमर पर एक मेखला के रूप में किये जा रहे खनन से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शिवालिक की इन पहाड़ियों पर कोढ़ पैदा हो गया है । इस नगर का प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो रहा है, जिसे तत्काल बचाया जाना आवश्यक है ।

स्थानीय लोगों द्वारा बराबर इस बात की मांग की जा रही है कि इस क्षेत्र में खनन कार्य को तत्काल बन्द किया जाये, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए ।

वर्तमान खनन अधिनियम पूर्णतः खानों के लीज धारकों के पक्ष में हैं । इस अधिनियम के तथा इसके उपबन्ध के रहते प्रदेश सरकार के लिए यह अनिवार्य सा है कि वह इच्छुक वर्तमान लीज धारक को पुनः एक बार और 20 वर्ष के लिए माईनिंग कार्य हेतु लीज प्रदान करे । मैं समझत हूं कि इस उपबन्ध को तत्काल समाप्त करना आवश्यक है ताकि प्रदेश सरकार समाप्त हो रही लीजों को रिन्यू न कर सके ।